



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-22] रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 सितम्बर, 2021 ई0 (भाद्रपद 20, 1943 शक सम्वत्) [संख्या-37

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

| विषय | पृष्ठ संख्या | वार्षिक चन्दा |
|---|--------------|---------------|
| | | रु0 |
| सम्पूर्ण गजट का मूल्य ... | — | 3075 |
| भाग 1-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ... | 487-489 | 1500 |
| भाग 1-क-नियम, कार्य-विधियां, आज़ाएँ, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ... | 357-361 | 1500 |
| भाग 2-आज़ाएँ, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के सन्दर्भ ... | — | 975 |
| भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ... | 05-09 | 975 |
| भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ... | — | 975 |
| भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ... | — | 975 |
| भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटीयों की रिपोर्ट ... | — | 975 |
| भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ... | — | 975 |
| भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ... | 263-271 | 975 |
| स्टोर्स पर्वेज-स्टोर्स पर्वेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ... | — | 1425 |

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग-1

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

25 अगस्त, 2021 ई०

संख्या 841/XXXI(1)/2021/पदो०-03/2020-उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतन लेवल-10 के रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) श्री प्रेम बल्लम डिमरी (दिव्यांग श्रेणी के अन्तर्गत दृष्टिगत ह्रास)
- (2) श्री धर्मेन्द्र सिंह पयाल
- (3) श्रीमती प्रियंका राणा
- (4) श्री विपिन कुमार

2-उपरोक्त अनुभाग अधिकारियों को 01 वर्ष की विहित परीक्षा पर रखा जाता है।

3-उक्त प्रोन्नति मा० लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 70/डी०बी०/2019 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4-उक्त पदोन्नत अनुभाग अधिकारियों की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

5-उक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग-01 में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

राधा रतूडी,
अपर मुख्य सचिव।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

अधिसूचना

05 अगस्त, 2021 ई०

संख्या 608/XXIV-C-3/2021-13(20)2018-राज्यपाल, सूरजमल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 (अधिनियम संख्या 15, वर्ष 2021) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 05 अगस्त, 2021 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करते हैं, जिस तारीख को उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

आज्ञा से,

दीपेन्द्र कुमार चौधरी,
सचिव (प्रभारी)।

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 608/XXIV-C-3/2021-13(20)2018**, dated August 05, 2021.

NOTIFICATION

August 05, 2021

No. 608/XXIV-C-3/2021-13(20)2018.— In exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 1 of the Surajmal University Act, 2021 (Act No. 15 of 2021), the Governor, hereby appoints 05th day of August, 2021 as the date on which the said Act shall come into force.

By Order,

DEEPENDRA KUMAR CHAUDHARI,

Secretary (incharge).



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 सितम्बर, 2021 ई0 (भाद्रपद 20, 1943 शक सम्वत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

August 10, 2021

No. 307/XIV/50/Admin.A--Shri Pradeep Pant, District & Sessions Judge, Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 32 days w.e.f. 18.06.2021 to 19.07.2021.

NOTIFICATION

August 13, 2021

No. 308/XIV/a-35/Admin.A/2015--Shri Amit Kumar, 2nd Additional Civil Judge (Sr. Div.) Hardwar is hereby sanctioned medical leave for 10 days w.e.f. 20.07.2021 to 29.07.2021.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

18th August, 2021

No. 310/UHC/VII-a-1/Stationery—The High Court of Uttarakhand and Subordinate Courts will remain closed on 20.08.2021 (Friday) on account of Moharram.

By Order of Hon'ble the Court,

Sd/-

Registrar General.

उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद्, देहरादून

नोटिस

17 अगस्त, 2021 ई०

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम-1965 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त लागू) (संशोधन) अधिनियम-2009 की धारा 28 एवं सहपठित धारा-56 के अन्तर्गत।

पत्रांक 385/उ०आ०वि०परि० पत्रा०सं०-130 (2021-22)—काशीपुर क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने हेतु उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् से "कनकपुर-काशीपुर PMAY आवासीय योजना" निदेशालय, शहरी विकास के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित की गयी, जो मै० साजिद नदीम प्र०, 107, तफैल गार्डन, कटोरा ताल, उधमसिंहनगर द्वारा भू-स्वामी, श्री जसवीर सिंह पुत्र श्री बलवन्तसिंह, कंवलजीत कौर पत्नी श्री जसबीर सिंह, निवासीगण मुरादाबाद रोड़ के०पी०सी० स्कूल के सामने काशीपुर, जिला उधमसिंहनगर के ग्राम कनकपुर तहसील काशीपुर के खसरा नं०-51, 52 मिन, क्षेत्रफल 2.8339 हे० में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत 1256 ई०डब्लू०एस० भवनों के निर्माण हेतु योजना प्रस्तुत की गई है। उक्त योजना पर भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

प्रस्तुत योजना हेतु भूमि का विवरण निम्नवत् है:-

| भूस्वामी का नाम | पता | प्रस्तावित स्थल/ग्राम का नाम | तहसील/जनपद | खसरा नं० | रकबा | योजना हेतु कुल रकबा |
|--|---|------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| श्री जसवीर सिंह पुत्र श्री बलवन्तसिंह, कंवलजीत कौर पत्नी श्री जसबीर सिंह | निवासीगण मुरादाबाद रोड़ के०पी०सी० स्कूल के सामने काशीपुर, जिला उधमसिंहनगर | ग्राम कनकपुर | तहसील काशीपुर जिला उधमसिंहनगर | खसरा नं०-51, 52 मिन | 1.2146 हे० 1.6193 हे० | 2.8339 हे० |

इस योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमायें निम्नवत् प्रकार है :-

उत्तर में 09 मीटर रास्ता, पूरब में रास्ता, दक्षिण में श्री रौनक सिंह का खेत 52 मि. एवं पश्चिम में श्री मुलकसिंह आदि का खेत नं०-50 और श्रीमती उमा देवी खेत नं०-51 मि. स्थित है।

उपरोक्त योजना का नक्शा, योजना का विवरण तथा प्रस्तावित भूमि का ब्यौरा उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् कार्यालय, राजीव गांधी बहुउद्देशीय काम्प्लेक्स पंचम तल, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून में किसी भी कार्यदिवस में 10:00 बजे पूर्वान्ह से 03:00 बजे अपरान्ह तक अथवा परिषद् की वेबसाइट <https://ukavp.org> पर देखा जा सकता है।

इस नोटिस के प्रथम बार प्रकाशित होने की तिथि 05 अगस्त, 2021 से छः सप्ताह के अन्दर योजना, ग्राम कनकपुर तहसील काशीपुर जनपद उधमसिंहनगर के खसरा नं०-51, 52 मि० क्षेत्रफल 2.8339 हे०, के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की आपत्तियाँ उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् कार्यालय राजीव गांधी बहुउद्देशीय काम्प्लेक्स पंचम तल, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून में प्रस्तुत की जा सकती हैं। प्रेषित आपत्तियों में योजना का सही-सही नाम, आपत्तिकर्ता का नाम, आपत्तिकर्ता की भूमि/भवन का पूर्ण विवरण यथा ग्राम का नाम, खसरा/प्लॉट संख्या, क्षेत्रफल व अन्य विवरण स्पष्ट रूप से सही-सही अंकित होना चाहिये।

नोटिस

17 अगस्त, 2021 ई०

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम-1965 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त लागू) (संशोधन) अधिनियम-2009 की धारा 28 एवं सहपठित धारा-56 के अन्तर्गत।

पत्रांक 385/उ०आ०वि०परि० पत्रा०सं०-130 (2021-22)-सितारगंज क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने हेतु उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् द्वारा "उकरौली-सितारगंज PMAY आवासीय योजना" प्रस्तावित हैं, जो मै० ग्रिप कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०, सी०एस०-01 ए, प्रथम तल उत्तरांचल प्लाजा, सेक्टर 2 बी, वसुन्धरा, गाजियाबाद, उ०प्र० द्वारा भू-स्वामी, श्री प्रवीण कुमार अरोड़ा पुत्र श्री किशन लाल अरोड़ा निवासी गाजियाबाद, श्री क्षितीज गुप्ता, पीताम्बर गुप्ता निवासी अशोक विहार, दिल्ली एवं श्री मूलचन्द अरोड़ा पुत्र कबूल चन्द अरोड़ा निवासी गढ़मीपुर तहसील रुड़की, हरिद्वार द्वारा ग्राम उकरौली, सितारगंज जिला उधमसिंहनगर के खसरा नं०-47/1मि०, 50, 48/2, 49/2मि०, 49/2मि० क्षेत्रफल 2.93 हे० में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत 1168 ई०डब्ल्यू०एस० भवनों के निर्माण हेतु योजना प्रस्तुत की गई। उक्त योजना पर भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

प्रस्तुत योजना हेतु भूमि का विवरण निम्नवत् है:-

| भूस्वामी का नाम | पता | प्रस्तावित स्थल/ग्राम का नाम | तहसील/जनपद | खसरा नं० | रकबा | योजना हेतु कुल रकबा |
|---|--|------------------------------|--------------------------|--|----------|---------------------|
| श्री प्रवीण कुमार अरोड़ा पुत्र श्री किशन लाल अरोड़ा श्री क्षितीज गुप्ता, पीताम्बर गुप्ता श्री मूलचन्द अरोड़ा पुत्र कबूल चन्द अरोड़ा | निवासीगण गाजियाबाद, अशोक विहार दिल्ली, गढ़मीपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार | ग्राम उकरौली | सितारगंज जिला उधमसिंहनगर | खसरा नं०-47/1, 50, 48/2, 49/2मि०, 49/2 | 2.93 हे० | 2.93 हे० |

इस योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमायें निम्नवत् प्रकार हैं-

उत्तर में खसरा सं०-44 अन्य भूमि, पूरब में खसरा नं०-46 अन्य भूमि, दक्षिण में रोड़ एवं पश्चिम में खसरा नं०-48 अन्य भूमि स्थित है।

उपरोक्त योजना का नक्शा, योजना का विवरण तथा प्रस्तावित भूमि का ब्यौरा उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् कार्यालय, राजीव गांधी बहुउद्देशीय काम्प्लेक्स पंचम तल, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून में किसी भी कार्यदिवस में 10:00 बजे पूर्वान्ह से 03:00 बजे अपरान्ह तक अथवा परिषद् की वेबसाइट <https://ukavp.org> में देखा जा सकता है।

इस नोटिस के प्रथम बार प्रकाशित होने की तिथि 05 अगस्त, 2021 से छः सप्ताह के अन्दर योजना, ग्राम उकरौली, सितारगंज, जिला उधमसिंहनगर के खसरा नं0-47/1, 50, 48/2, 49/2 मि0, 49/2 क्षेत्रफल 2.93 हे0, के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की आपत्तियाँ उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् कार्यालय राजीव गांधी बहुउद्देशीय काम्प्लेक्स पंचम तल, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून में प्रस्तुत की जा सकती है। प्रेषित आपत्तियों में योजना का सही-सही नाम, आपत्तिकर्ता का नाम, आपत्तिकर्ता की भूमि/भवन का पूर्ण विवरण यथा ग्राम का नाम, खसरा/ प्लॉट संख्या, क्षेत्रफल व अन्य विवरण स्पष्ट रूप से सही-सही अंकित होना चाहिये।

नोटिस

17 अगस्त, 2021 ई0

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम-1985 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त लागू) (संशोधन) अधिनियम-2009 की धारा 28 एवं सहपठित धारा-56 के अन्तर्गत।

पत्रांक 385/उ0आ0वि0परि0 पत्रा0सं0-130 (2021-22)-रूद्रपुर क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने हेतु उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् द्वारा "बिगवाड़ा-रूद्रपुर PMAY आवासीय योजना" प्रस्तावित है, जो दून प्राईम एसोसिएट्स प्रा0लि0 175 बी, हरिद्वार रोड, देहरादून द्वारा भू-स्वामी, श्री निरवैर सिंह पुत्र साहब सिंह, प्रकट सिंह पुत्र साहब सिंह निवासी ग्राम बिगवाड़ा तहसील रूद्रपुर जिला उधमसिंहनगर के खसरा नं0-192/1, 192/2, 200, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 व 210/1 क्षेत्रफल 2.6299 हे0 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत 1144 ई0डब्लू0एस0 भवनों के निर्माण हेतु योजना प्रस्तावित की गई। उक्त योजना पर भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

प्रस्तुत योजना हेतु सम्मिलित भूमि का विवरण निम्नवत् है:-

| भूस्वामी का नाम | पता | प्रस्तावित स्थल/ग्राम का नाम | तहसील/जनपद | खसरा नं0 | रकबा | कुल रकबा |
|--|--|------------------------------|--------------------------------|--|-----------|------------|
| श्री निरवैर सिंह पुत्र साहब सिंह, प्रकट सिंह पुत्र साहब सिंह | निवासीगण ग्राम बिगवाड़ा तहसील रूद्रपुर जिला उधमसिंहनगर | ग्राम बिगवाड़ा | तहसील रूद्रपुर जिला उधमसिंहनगर | खसरा नं0-192/1, 192/2, 200, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, व 210/1 | 6.055 हे0 | 2.6299 हे0 |

इस योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमायें निम्न प्रकार है-

पार्ट-A: उत्तर में चक रोड, पूरब में मास्टर प्लान में हरित जोन, दक्षिण में मास्टर प्लान 24 मी0 महायोजना रोड एवं पश्चिम में अन्य भूमि स्थित है।

पार्ट-B: उत्तर में मास्टर प्लान 24 मी० महायोजना रोड, पूरब में आवेदक की अन्य भूमि, दक्षिण में अन्य भूमि एवं पश्चिम में अन्य भूमि स्थित है।

उपरोक्त योजना का नक्शा, योजना का विवरण तथा प्रस्तावित भूमि का ब्यौरा उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् कार्यालय, राजीव गांधी बहुउद्देशीय काम्प्लेक्स पंचम तल, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून में किसी भी कार्यदिवस में 10:00 बजे पूर्वान्ह से 03:00 बजे अपरान्ह तक अथवा परिषद् की वेबसाइट <https://ukavp.org> में देखा जा सकता है।

इस नोटिस के प्रथम बार प्रकाशित होने की तिथि 05 अगस्त, 2021 से छः सप्ताह के अन्दर योजना, ग्राम बिगवाड़ा तहसील रुद्रपुर जिला उधमसिंहनगर के खसरा नं०-192/1, 192/2, 200, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 व 210/1 क्षेत्रफल 2.6299 हे०, के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की आपत्तियाँ उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् कार्यालय राजीव गांधी बहुउद्देशीय काम्प्लेक्स पंचम तल, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून में प्रस्तुत की जा सकती है। प्रेषित आपत्तियों में योजना का सही-सही नाम, आपत्तिकर्ता का नाम, आपत्तिकर्ता की भूमि/भवन का पूर्ण विवरण यथा ग्राम का नाम, खसरा प्लॉट संख्या, क्षेत्रफल व अन्य विवरण स्पष्ट रूप से सही-सही अंकित होना चाहिये।

डा० अभिषेक त्रिपाठी,
अपर आवास आयुक्त।

कार्यालय संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विज्ञप्ति

25 सितम्बर, 2020 ई०

संख्या 8001/तीन-चक०सं०/रा०प०/2020-उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग-3, देहरादून के शासनादेश संख्या-632/XVIII(3)2020-04(08)/2018, दिनांक 17 सितम्बर, 2020 से प्राप्त अनुमति के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं बाल मयंक मिश्र, संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद उधमसिंह नगर की तहसील बाजपुर एवं किच्छा के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं :-

| क्र०सं० | जनपद | तहसील | ग्राम |
|---------|-------------|--------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | उधमसिंह नगर | बाजपुर | सीटनगंज |
| 2. | —तदैव— | किच्छा | श्रीपुर |

बी०एम० मिश्र,
संचालक चकबन्दी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 37 हिन्दी गजट/372-भाग 1-क-2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 सितम्बर, 2021 ई० (भाद्रपद 20, 1943 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

निदेशालय पंचायतीराज,

उत्तराखण्ड देहरादून

03 जून, 2021 ई०

कार्यालय ज्ञाप

संख्या 143/933/जि०प०अ०को०/2021-22—जिला पंचायत, देहरादून की नियोजन एवं विकास समिति की बैठक दिनांक 14.12.2020 एवं जिला पंचायत की बोर्ड बैठक दिनांक 19.12.2020 में पारित प्रस्ताव के आधार पर जिला पंचायत देहरादून द्वारा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (अधिनियम सं०-11, वर्ष 2016) के भाग-4 की धारा 108 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत देहरादून के उन क्षेत्रों जो नगर निकाय, छावनी परिषद्, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण या अन्य किसी प्राधिकरण के अधिकारी क्षेत्र में हैं, को छोड़कर जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों/बाजारों में निजी आवासीय भवनों, व्यापारिक/व्यावसायिक भवनों, होटल, मोटल, 03 सितारा होटल, 05 सितारा होटल, रज्जू मार्ग, झूला घर, मनोरंजन केन्द्र, सिनोमाघर, मॉल आदि भवनों के भवन मानचित्र (नक्शा) स्वीकृत/अनुमोदित किये जाने के सम्बन्ध में नवीन उपविधियों बनाई गई हैं।

एतद्वारा अधिनियम की धारा-149(ग)(4) द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निदेशक, पंचायतीराज उत्तराखण्ड देहरादून के रूप में उक्त उपविधियों की शासकीय गजट में प्रकाशनार्थ पुष्टि की जाती है। यह उपविधियां उत्तराखण्ड के शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

कार्यालय जिला पंचायत, देहरादून।

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2016) के भाग-4 अध्याय-19 की धारा 106 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, देहरादून उन क्षेत्रों जो नगर निकाय, छावनी परिषद, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण या अन्य किसी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में हैं, को छोड़कर जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों/बाजारों में निजी आवासीय भवनों, व्यापारिक/व्यवसायिक भवनों, होटल, मोटल, 03 सितारा होटल, 05 सितारा होटल, रज्जू मार्ग, झूला घर, मनोरंजन केन्द्र, सिनेमाघर, मॉल आदि का मानचित्र (नक्शा) स्वीकृत/अनुमोदित किये जाने हेतु निम्नलिखित उपविधि बनाती है।

उपविधियाँ

1. ये उपविधियाँ जिला पंचायत देहरादून की भवन मानचित्र (नक्शा) स्वीकृत/अनुमोदित किये जाने संबंधी उपविधियों, 2021 कहलाई जायेंगी।
2. ये उपविधियाँ विधिपूर्वक पुष्टि होने के उपरान्त सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी।
3. ये उपविधियाँ जनपद देहरादून के उन क्षेत्रों जो किसी नगर निकाय, छावनी परिषद, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण या अन्य किसी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में हैं, को छोड़कर जनपद के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होंगी।
4. परिभाषाएँ— इन उपविधियों में—
 - (1) “अधिनियम” का तात्पर्य उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 से है।
 - (2) “ग्रामीण क्षेत्र” का तात्पर्य उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा-2 (3) में परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र से है।
5. कोई भी व्यक्ति, फर्म, संस्था, कम्पनी, इत्यादि जिला पंचायत, देहरादून के क्षेत्रान्तर्गत निजी आवासीय भवनों, व्यापारिक/व्यवसायिक भवनों, होटल, मोटल, 03 सितारा होटल, 05 सितारा होटल, रज्जू मार्ग, झूला घर, मनोरंजन केन्द्र, सिनेमाघर, मॉल इत्यादि का निर्माण तब तक नहीं करेंगे, जब तक कि उस व्यक्ति, फर्म, संस्था, कम्पनी, इत्यादि द्वारा जिला पंचायत, देहरादून से उसका मानचित्र स्वीकृत/अनुमोदित न करवा लिया हो।
6. जिला पंचायत, देहरादून के क्षेत्रान्तर्गत निजी आवासीय भवनों, व्यापारिक/व्यवसायिक भवनों, होटल, मोटल, 03 सितारा होटल, 05 सितारा होटल, रज्जू मार्ग, झूला घर, मनोरंजन केन्द्र, सिनेमाघर, मॉल इत्यादि के निर्माण में निम्नलिखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा :-
 - (क) प्रत्येक निजी आवासीय भवनों, व्यापारिक/व्यवसायिक भवनों, होटल, मोटल, 03 सितारा होटल, 05 सितारा होटल, रज्जू मार्ग, झूला घर, मनोरंजन केन्द्र, सिनेमाघर, मॉल इत्यादि का निर्माण मुख्य सड़क के मध्य से 33 फिट या नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के सड़क अतिक्रमण क्षेत्र से बाहर, जो भी दूरी अधिक हो, के बाद किया जायेगा।
 - (ख) निर्माण कार्य से सड़क की नाली आदि में अतिक्रमण न हो।
 - (ग) निजी आवासीय भवनों, व्यापारिक/व्यवसायिक भवनों, होटल, मोटल, 03 सितारा होटल, 05 सितारा होटल, रज्जू मार्ग, झूला घर, मनोरंजन केन्द्र, सिनेमाघर, मॉल इत्यादि का निर्माण भूकम्परोधी होना चाहिए, एवं पर्यावरण संरक्षण का पूर्ण ध्यान रखना अनिवार्य होगा, उपरोक्त के समीप छायादार/हवादार पेड़, उचित हिस्से में हरियाली/वृक्षारोपण तथा रोड़ साइड कंट्रोल एक्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लॉन्ट लगाये जाने अनिवार्य होंगे।
 - (घ) उत्तराखण्ड सरकार की आवासीय नीति भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम 2011, उत्तराखण्ड यथा संशोधित 2017 में निर्धारित प्राविधानों के अन्तर्गत ही मानचित्र स्वीकृत/अनुमोदित किया जायेगा।
 - (ङ) भूमि सम्बन्धी सरकारी/गैर सरकारी कोई भी विवाद उठने पर निर्माण कार्य के निर्माणकर्ता की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
 - (च) मकान, भवन, होटल इत्यादि के रसोई घर की चिमनी खुली हवा की ओर रखनी अनिवार्य होगी ताकि आस-पास रहने वालों पर किसी प्रकार का कोई कुप्रभाव न पड़े, इसके अतिरिक्त शौचालय व पेशाब घर निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने होंगे तथा उनकी निकासी यदि सीवर लाइन हो तो उससे जोड़ना होगा। अगर सीवर लाइन न हो तो

सोखा गडढा एव सेप्टिक टैंक ऐसे सुरक्षित स्थान पर बनाया जायेगा, जिससे नदी, नाले तथा अन्य को किसी हानि या प्रदूषण/गन्दगी का सामना न करना पड़े। सफाई व्यवस्था का पर्याप्त ध्यान रखना अनिवार्य होगा।

(घ) होटल/व्यवसायिक/आवासीय भवनों में कार/बस इत्यादि की पार्किंग की समूचित व्यवस्था करनी अनिवार्य होगी।

7. नक्शा स्वीकृति/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे :-

- (1) नक्शा स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र।
- (2) आवेदक के मान्य पहचान पत्र की स्व हस्ताक्षरित प्रति यथा आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स इत्यादि।
- (3) क्षेत्रीय पटवारी की तस्दीक रिपोर्ट/आख्या उस जगह की जिस क्षेत्र में व्यवसायिक प्रतिष्ठान बनाया जाना है।
- (4) लीज, सैलडीड, पॉवर ऑफ अटॉर्नी, दाखला नकल खाता खतौनी की छायाप्रति।
- (5) जमीन रजिस्ट्री की छायाप्रति।
- (6) क्षेत्रीय ग्राम समा के प्रधान की संस्तुति।
- (7) भूकम्परोधी निर्माण हेतु वास्तुविद/संरचनात्मक इंजीनियर का प्रमाण-पत्र।
- (8) नक्शा वास्तुविद एवं संरचनात्मक इंजीनियर की मुहर तथा विस्तृत ड्राइंग डिजाइन के साथ संलग्न करना होगा।
- (9) 100 रुपये का स्टाम्प।
- (10) बिल्डिंग बायलॉज (Bye laws) के अनुसार निर्माण किये जाने संबंधी प्रमाण-पत्र।
- (11) सुरक्षा उपाय एवं अग्निशमन हेतु विस्तृत प्लान।
- (12) 02 पासपोर्ट साइज फोटो।

8. उपरोक्त समस्त औपचारिकताएं एवं इस उपविधि में निर्धारित शर्तें पूर्ण होने के उपरान्त निर्धारित फीस जमा कराने के दिनांक से 15 दिन के अन्तर्गत नक्शा स्वीकृति/अनुमोदित किया जायेगा।

9. जिला पंचायत, देहरादून के क्षेत्रीय कनिष्ठ अभियन्ता, क्षेत्रीय कर निरीक्षक एवं कर अधिकारी की आख्या एवं अभियन्ता, जिला पंचायत की संस्तुति पर जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी, उपरोक्त उद्देश्य से किये जाने वाले निर्माण कार्य के मानचित्र/नक्शा स्वीकृत करने के अधिकारी होंगे।

10. जनपद देहरादून के जिला पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में निजी आवासीय तथा व्यापारिक/व्यावसायिक उद्देश्य से निर्मित किये जाने वाले निजी आवासीय भवनों, व्यापारिक/व्यवसायिक भवनों, होटल, मोटल, 03 सितारा होटल, 05 सितारा होटल, रज्जू मार्ग, झूला घर, मनोरंजन केन्द्र, सिनेमाघर, मॉल आदि के स्वामी को उपरोक्त उपविधियों का पालन करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त किसी भी उपविधि का उल्लंघन करने पर जिला पंचायत, देहरादून ऐसे व्यक्ति, फर्म, संस्था आदि के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होगी।

11. व्यापारिक/व्यवसायिक भवनों का निर्माण पूर्ण होने पर तथा उनके चालू होने पर जिला पंचायत द्वारा आरोपित लाइसेन्स शुल्क एवं सम्पत्ति विभव कर प्रतिवर्ष जमा करना अनिवार्य होगा।

12. उक्त के अतिरिक्त कुछ अन्य निम्नलिखित शर्तों का भी आवश्यक रूप से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

(क) विद्युत लाइन से दूरी-

| क. सं. | विद्युत लाइन का प्रकार | Minimum Vertical Clearance | Horizontal Clearance |
|--------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1. | कम एवं मध्य वोल्टेज लाइन से | 2.50 मीटर | 1.20 मीटर |
| 2. | High Voltage line up to 11000 Volts | 3.70 मीटर | 1.20 मीटर |
| 3. | High Voltage line Above 11000 Volts | 3.70 मीटर | 2.0 मीटर |

(ख) जल स्रोत से दूरी-

- | | | |
|--|---|-----------|
| 1. नदी के किनारे से | — | 30 मीटर। |
| 2. Under Ground Water Source/ झरना | — | 10 मीटर। |
| 3. नाला/प्राकृतिक धारा (Natural water channel) | — | 5.0 मीटर। |
| 4. झील की बाउन्ड्री से | — | 30 मीटर। |

(ग) भवन मानचित्र की आवश्यक सैट बैक शर्तें

1. भवन के तीन ओर न्यूनतम 0.90 मीटर का Set Back.
2. भवन के अग्र भाग में न्यूनतम 1.80 मीटर F.S.B
3. भवन की ऊँचाई मुख्य सड़क से लगे होने की दशा में सड़क के कोने से 45° से अधिक न जाए।
4. सामान्य भवन की ऊँचाई पहाड़ी क्षेत्रों में 11.00 मीटर से अधिक न हो एवं मैदानी भागों में 30.00 मीटर से अधिक न हो या सरकार द्वारा समय-समय पर पारित दिशा निर्देशों के अनुसार।
5. निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जायेगा। अन्यथा की दशा में आवेदनकर्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे।
6. निर्माण कार्य के दौरान पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा तथा भूजल का दोहन नहीं किया जायेगा।
7. नक्शा अनुमोदन की तिथि से तीन वर्ष के भीतर निर्माण कार्य सम्पन्न करना होगा, अन्यथा की दशा में स्वीकृति को निरस्त माना जायेगा, तथा स्वीकृति हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
8. जल संस्थान/उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन/पर्यावरण कंट्रोल बोर्ड/अग्निशमन आदि विभागों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने की जिम्मेदारी आवेदनकर्ता की स्वयं की होगी।
9. शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही का अधिकार जिला पंचायत के सक्षम प्राधिकारियों में निहित होगा।

नक्शा/मानचित्र स्वीकृति/अनुमोदन हेतु निर्धारित शुल्क

| क्र०सं० | भवन का प्रकार | पहाड़ी क्षेत्र | मैदानी भाग |
|---------|---|--|--------------------|
| 1 | सामान्य आवासीय भवन | रुपये 10/वर्ग मीटर। | रुपये 15/वर्ग मीटर |
| 2 | सामान्य बहुदरिणीय भवन | रुपये 20/वर्ग मीटर। | रुपये 30/वर्ग मीटर |
| 3 | होटल एवं व्यावसायिक भवन | रुपये 40/वर्ग मीटर। | रुपये 60/वर्ग मीटर |
| 4 | मनोरन्जन पार्क (कवर्ड क्षेत्रफल) | रुपये 40/वर्ग मीटर। | रुपये 60/वर्ग मीटर |
| 5 | मनोरन्जन पार्क (कवर्ड क्षेत्रफल के अतिरिक्त खुली भूमि पर) | कुल भूमि क्षेत्रफल का रुपये 10/वर्ग मीटर | रुपये 10/वर्ग मीटर |
| 6 | रज्जू मार्ग | रुपये 5000/100 मीटर | |

दरें कवर्ड क्षेत्रफल द्वारा आंगणित पूर्ण क्षेत्रफल पर हर मंजिल के लिये लगाई जायेगी। तथा सीढ़ी का क्षेत्रफल केवल भूमि तल में लिया जायेगा।

बिना अनुमति निर्मित आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के शमन शुल्क की दरें

| क्र० सं० | घटक | मुखण्ड का क्षेत्रफल | एकल आवासीय | | गैर आवासीय | |
|----------|---|--|--|--|---|--|
| | | | पहाड़ी क्षेत्र | मैदानी क्षेत्र | पहाड़ी क्षेत्र | मैदानी क्षेत्र |
| 1 | अनुमन्य भू आच्छादन तक क्षेत्र समानुपात के अन्तर्गत बिना अनुमति निर्माण करने पर। | (1) 0 से 60 वर्ग मी० प्लॉट एरिया तक के मुखण्ड। | रुपये 41/वर्ग फीट (कुल प्लॉट क्षेत्रफल) | रुपये 42 /वर्ग फीट (कुल प्लॉट क्षेत्रफल) | रुपये 43.50/ वर्ग फीट (कुल प्लॉट क्षेत्रफल) | रुपये 45/ वर्ग फीट (कुल प्लॉट क्षेत्रफल) |
| | | (2) 60 से 112.50 वर्ग मी० प्लॉट एरिया तक के मुखण्ड। | रुपये 42 /वर्ग फीट (कुल प्लॉट क्षेत्रफल) | रुपये 43/वर्ग फीट (कुल प्लॉट क्षेत्रफल) | रुपये 45 / वर्ग फीट (कुल प्लॉट क्षेत्रफल) | रुपये 50/ वर्ग फीट (कुल प्लॉट क्षेत्रफल) |
| | | (3) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकृति के निर्माण के लिये। | रुपये 43.5 /वर्ग फीट (कुल प्लॉट क्षेत्रफल) | रुपये 45.50 / वर्ग फीट (कुल प्लॉट क्षेत्रफल) | रुपये 47.50/ वर्ग फीट (कुल प्लॉट क्षेत्रफल) | रुपये 55/ वर्ग फीट (कुल प्लॉट क्षेत्रफल) |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| 2 | अग्र सैटबैक (Front Setback) | रुपये 155 /वर्ग फीट (अतिरिक्त आच्छादित क्षेत्रफल) | रुपये 160 / वर्ग फीट (अतिरिक्त आच्छादित क्षेत्रफल) | रुपये 162 /वर्ग फीट (अतिरिक्त आच्छादित क्षेत्रफल) | रुपये 170 / वर्ग फीट (अतिरिक्त आच्छादित क्षेत्रफल) |
| 3 | पीछे के सैटबैक पर (Rear Setback) व पार्श्व सैटबैक (Side Setback) | रुपये 150 /वर्ग फीट (अतिरिक्त आच्छादित क्षेत्रफल) | रुपये 155 /वर्ग फीट (अतिरिक्त आच्छादित क्षेत्रफल) | रुपये 158 /वर्ग फीट (अतिरिक्त आच्छादित क्षेत्रफल) | रुपये 165 / वर्ग फीट (अतिरिक्त आच्छादित क्षेत्रफल) |
| 4 | यदि भवन की अन्तरिम ऊँचाई 10 प्रतिशत तक हो। | रुपये 5 /वर्ग फीट (कुल आच्छादित क्षेत्रफल) | रुपये 7.50 /वर्ग फीट (कुल आच्छादित क्षेत्रफल) | रुपये 8 /वर्ग फीट (कुल आच्छादित क्षेत्रफल) | रुपये 10 /वर्ग फीट (कुल आच्छादित क्षेत्रफल) |
| 5 | अतिरिक्त भू-आच्छादन (Ground Coverage) | रुपये 50 /वर्ग फीट | रुपये 55 /वर्ग फीट | रुपये 65 /वर्ग फीट | रुपये 75 / वर्ग फीट |
| 6 | अनुमत्य भू-आच्छादन के अन्तर्गत अतिरिक्त तल क्षेत्र समानुपात पर। | रुपये 50 /वर्ग फीट (कुल प्लॉट क्षेत्रफल आच्छादित) | रुपये 52.50 /वर्ग फीट (कुल प्लॉट क्षेत्रफल आच्छादित) | रुपये 60 /वर्ग फीट (कुल प्लॉट क्षेत्रफल आच्छादित) | रुपये 75 / वर्ग फीट (कुल प्लॉट क्षेत्रफल आच्छादित) |

शारि

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2016) के भाग-4 अध्याय-19 की धारा 147 से 149 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह हिदायत दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करता है तो जुर्माने से जो 1,000/- (रु0 एक हजार) तक हो सकता है, दण्डनीय होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो वह एक ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम बार दोषसिद्धि की तिथि के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरन्तर किया जाना सिद्ध हो, 100/- (रु0 एक सौ) तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

राजीव कुमार नाथ त्रिपाठी,
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, देहरादून।

हरिचन्द्र सेमवाल,
निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तराखण्ड देहरादून।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 सितम्बर, 2021 ई0 (भाद्रपद 20, 1943 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर पंचायत गंगोत्री उत्तरकाशी

28 जून, 2021 ई0

पत्रांक 1822/21-फे0स0उ0-स0 गजट-प्र0/2021-22-नगर पंचायत गंगोत्री उत्तरकाशी की सीमान्तर्गत उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1918 की धारा-298 जो (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की उप धारा-2 खण्ड (01) (ग) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए धारा-128 की उपधारा-1 (ii) (iii) शक्तियों का प्रयोग करते हुए "फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबन्धकीय उपनियम 2020 बनायी जाती है, जो नगरपालिका अधिनियम-1918 की धारा 301 (1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव 30 दिन के अन्तर्गत आमंत्रित किये जाते हैं निर्धारित समय के अन्तर्गत कोई भी आपत्ति एवं सुझाव नगर पंचायत गंगोत्री को प्राप्त न होने के फलस्वरूप नगर पंचायत गंगोत्री द्वारा उक्त उपविधि को अन्तिम रूप स्वीकार करते हुए उपविधि को सरकारी गजट में प्रकाशन तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

अध्याय-1

सामान्य

1- संक्षिप्त नाम और लागू होने की तिथि:

(1) ये उपनियम नगर पंचायत गंगोत्री के फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबन्धकीय उपनियम -2020 कहलायेगा ।

(2) ये उपनियम नगर पंचायत गंगोत्री के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी ।

4- उपनियम नगर पंचायत गंगोत्री की सीमाओं के भीतर लागू होंगे ।

1- प्रसंग :

यह महत्वपूर्ण है कि एक उचित वैज्ञानिक प्रबंध इन मामलों में / सेप्टेज का अनुपालन किया जाय , ताकि सेप्टेज / फेकल सलज सेप्टिक टैंक , गड्ढे , शौचालय से पर्यावरण नदी एवं अन्य पानी के स्रोत प्रदूषित न हो सके ।

1.1- राष्ट्रीय फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय नीति : ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार " राष्ट्रीय फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंध नीति ' वर्ष 2019 घोषित की गई है , जिसमें शहर पूर्ण रूप से स्वच्छ , तंदुरस्त और जीवित बने रहे और अच्छी सफाई भी बनी रहे । शहरी नीति का मुख्य उद्देश्य एक प्रसन्न , प्राथमिकता और दिशा निर्धारित करनी है , ताकि राष्ट्रीयव्यापी अनुपालन इन सेवाओं का समस्त क्षेत्र सुरक्षित और स्थाई सफाई व्यवस्था हो सके ।

1.2- उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकॉल : नगर पंचायत गंगोत्री में " उचित प्रबंध योजना या प्रोटोकॉल सीवरेज की निकासी जो कि सामान्य सैप्टिक टैंक में या बायो डाइजेस्टर में एकत्रित की जाती है . नियमित रूप से खाली की जाय और उसका उचित प्रबंध किया जाये और उसके परिणाम स्वरूप खाद जो इस प्रकार से एकत्रित हुई है , वह निशुल्क किसानों में वितरित की जायेगी । जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1975 / नगर पालिका अधिनियम 1916 शहरी विकास निदेशालय जो की उत्तराखण्ड जल संस्थान के समन्वय से होगा , इसके लिए

प्राटोकल सेप्टेज प्रबन्ध तैयार किया है , जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सूचित किया गया है , ताकि इस का अनुपालन शहरों / नगरों में हो सके । आदेश संख्या- 597/4 (2) -यू 0 डी0-2017-50 / 16 दिनांक 22-05-2017 इस नियामावली का सेप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकल गंगोत्री शहर को दिग्दर्शन कराना है , ताकि वैज्ञानिक सेप्टेज प्रबन्ध बना रहे , जो कि एकत्रीकरण , परिवहन , इलाज , सेप्टेज / फेकल सलज का निस्तारण और पुनः प्रयोग हो सके । इस प्रोटोकल के प्रभावी कियान्वयन के लिए और आन्तरिक विभागीय समन्वय हेतु एक सेप्टेज मैनेजमेन्ट सेल का आयोजन किया गया है , जिसके अन्तर्गत यू ० एल 0 बी 0 जल निगम जल संस्थान होंगे ।

2-नगरीय उप कानून / फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबन्ध का नियमितिकरण : सेप्टेज प्रबन्ध प्राटोकल के अनुसार जो कि शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या -597 IV (2) - श 0 वि0-2017-50 (सा) / 16 दिनांक 22-05-2017 एवं समस्त लागू होने योग्य नियम कानून या नगर पंचायत गंगोत्री नियमित ढांचा रिक्त करने , एकत्र करने परिवहन और सेप्टेज / फेकल सलज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि संदर्भित है । फेकल सलज अनुपालन हेतु नगर पंचायत गंगोत्री के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सूचित किया जाता है।

3-उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र :

नियमावली के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र निम्नवत है-

1. निर्माण सेप्टिक टैंक के दैनिक रख - रखाव और शौचालय के गड्ढे , परिवहन , इलाज और सुरक्षित रखरखाव , जो कि सलज और सेप्टेज से सम्बन्धित है ।
2. क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है , उसको निर्देशित करना जो कि सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से और फेकल सलज एवं सेप्टेज परिवहन से सम्बन्धित है , ताकि वे इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकें ।\
3. उचित निरीक्षण प्रदान करना और मशीनरी का अनुपालन ।
4. लागत वसूली सुनिश्चित करना जो कि सलज के और सेप्टेज प्रबन्ध के अचित प्रबंध हेतु है ।
5. निजी और गैर सरकारी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबन्ध में सहभागी की सुविधा देना ।

4- एकत्रीकरण , परिवहन , इलाज और सेप्टेज के खुर्द - बुर्द हेतु एक प्रक्रिया

अपनाना:

4.1- सेप्टिक टैंक और सेप्टेज / फेकल सलज एकत्रीकरण को रिक्त करना: सेप्टिक टैंक की तली में जा जमा हो गया है , उसको कटाना और एक बार उसको ठीक करना , जो कि गहराई में पहुंच गया है , या बारंबार के आखिर में जो डिजाइन है , जो कोई भी पहले आवे । जबकि सलज को सुखाना और सेप्टिक टैंक में जो द्रव्य है , उसको भी सुखाना । मै केनिकल वेक्यूम टैंकर का भी उपयोग नगरीय अधिकारियों द्वारा सेप्टिक टैंक को खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए । सुरक्षा प्रक्रिया जैसा कि सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकॉल में वर्णित है , को सेप्टिक टैंक के खाली करते समय और सेप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का शख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

4.2-सेप्टेज / फेकल सलज का परिवहन :-

1- फेकल सलज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होंगे । जैसा कि समय - समयपर एस • एम • सी • द्वारा स्वीकृत किये जायेगे ।

2 :- फेकल सलज और सेप्टेज परिवहन निर्माता यह आवश्यक सन देंगे कि :

अ- पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अन्तर्गत समस्त उपकरण जो कि फेकल सलज और सेप्टेज हेतु इस्तेमाल किये जायेंगे छिद्र निरोधी होगा और सुरक्षा हेतु ताला बंद रहेगा और मानदंड का अनुपालन करेगे ।

ब- कोई भी टैंक और उपकरण जो फेकल सलज और सेप्टेज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु इस्तेमाल नहीं किया जायेगा ।

4.3 :- सेप्टेज का निष्पादन और इलाज :-

राज्य सेप्टेज का मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के अनुसार प्रत्येक नगर की अपनी एक इकाई होगी । परन्तु इस निकाय में इकाई न होने के कारण सेप्टेज को निकाय से 35 कि 0 मी 0 दूर अन्तर्गत स्थित नजदीकी उत्तराखण्ड जल संस्थान के एस 0 टी 0 पी 0 में परिवहन किया जायेगा । भविष्य हेतु एक अलग सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लान का निर्माण हेतु भी कार्ययोजना तैयार कराने के प्रयास किये जायेंगे ।

5 सुरक्षा उपाय :

1. उचित तकनीकी सयंत्र सुरक्षा उपकरण का प्रयोग करते हुए मल निस्तारण किया जायेगा। फेकल सलज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर यह आशान्वित करेंगे समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जिसके अन्तर्गत कंधे की लम्बाई तक नियोपीन गलन्स रबड़, बूट, चेहरे का मास्क और आंखों की सुरक्षा समस्त उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जायेगा। इसके लिये जागरुकता भी की जायेगी। इसके उलावा प्रथम सहायता किट, गैस का पता करने वाला लैंप और अग्निशामक यंत्र मल निस्तारण गाड़ी में रखे जायेगे। जब सेप्टिक टैंक और पिट लैंड्रिन में काम चल रहा हो धूमपान वर्जित रहेगा।

2.- मल निस्तारण कार्यकर्ता सेप्टिक टैंक में और शौचालय गड्ढे में प्रवेश नहीं करेंगे औ आच्छादित टैंक को हवा के लिए आना - जाना रखेंगे, जो कि इस कार्य को शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक होगा। बच्चों का टैंक के ढक्कन से दूर रखा जायेगा एवं टैंक के स्कू और ताले से सुरक्षित रखा जाये। कर्मचारी सावधान रहेंगे कि मल निस्तारण प्रक्रिया के समय ढक्कन पर अत्यधिक भार न हो ताकि मेन हॉल का ढक्कन टूटने से बचा रहें।

6- सेप्टेज खाली करना और वाहन के पंजीकरण का परिवहन :

6.1 -यू० एल० बी० दर्ज करेगा और लाईसेंस निर्गत करेगा निजी व्यवसायों के लिए जिनके पास, मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाड़ी उपलब्ध हो। इस प्रकार का लाईसेंस निर्गत करने से पहले यह आशान्वित करेगा कि उचित उपकरण और उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है। सेप्टेज ट्रांसपोर्टर और उसका पंजीकरण हेतु प्रार्थना - पत्र प्रस्तुत करेगा, जो कि गाड़ियों के परिवहन हेतु होगा। ये निजी व्यक्ति को भी अपने इस कार्य में उत्साहित करेंगे पंजीकरण प्रपत्र और परमिट परिशिष्ट - ए. 2 में संलग्न है।

6.2 कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रयोग किया जायेगा, जो कि एकत्रीकरण परिवहन और सेप्टेज के प्रयोजन हेतु है। जब तक इसका पंजीकरण सेप्टेज ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल एस० एम० सी० के साथ इन प्रोटोकॉलों में जब तक पंजीकृत नहीं है।

सरणी 1 पंजीकरण व्यय

| | | |
|-----|--------------------|---------------------------|
| अ.- | प्रारम्भिक पंजीकरण | रु 0 2,000.00 प्रति गाड़ी |
| ब.- | नवीनीकरण | रु 0 1,500.00 प्रति गाड़ी |

7.- उपभोक्ता लागत और इसका संचय:

7.1- इस क्षेत्र के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि यू० एल 0 बी 0 में फेकल सलज और सेप्टेज उपनियम में समय - समय पर दर्शाया गया है जो कि सेप्टिक टैंक के भरने, शौचालय के गड्ढे, परिवहन और फेकल सलज एवं सेप्टेज के उपाय हेतु है।

7.2- इस क्षेत्र के समस्त मालिक जिनके अपने क्षेत्र में निरर्थक पानी के निष्कासन की प्रणाली उपलब्ध है, जो कि यू० एल 0 बी 0 कार्य एवं शिकायत हेतु प्रमाणित है और वे भी जो कि सीवर नेटवर्क से सम्बन्धित है, उनको उनके उपभोक्ता के भुगतान से विमुक्त किया जाता है।

7.3- यू० एल 0 बी 0 में अपनी लागत संशोधित करेगा, जो कि समय - समय पर इससे सम्बन्धित है। ऐसी उपभोक्ता लागत जिसके अन्तर्गत मल निस्तारण लागत परिवहन एवं फेकल सलज और सेप्टेज के निष्कासन हेतु।

7.4 उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्वामी से एकत्र किये जाये जो निम्नवत हैं।

अ.- उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धि भवन / सेप्टिक टैंक मालिक से यू 0 एल 0 बी 0 द्वारा वसूल कर यू० एल 0 बी 0 में जमा किया जायेगा।

ब.- यू० एल 0 बी 0 किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है, जिसके अन्तर्गत फेकल सलज और सेप्टेज परिवहन जो कि उपभोक्ता लागत से एकत्र की जायेगी। जो कि उस क्षेत्र विशेष का स्वामी है और सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से सम्बन्धित है।

सारणी 2 :- उपभोक्ता लागत:

नगर पंचायत क्षेत्र में सैप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गड्ढे या किसी भी शिकायत के इस आशय की शिकायत प्राप्त होने पर कि सैप्टिक टैंक ओवर - फ्लो तो नहीं हो रहा है तुरन्त नगर पंचायत से सुपरवाइजर को भेज कर जांच करवायेगे। इसके अलावा नगर पंचायत में सैप्टिक टैंक को खाली कराने के आवेदन के आने पर नगर पालिका द्वारा जाँच करायी जायेगी कि सैप्टिक टैंक कितना क्षेत्रफल का है और उसके खाली कराने में कितने सीवर टैंकर के चक्कर लगेंगे। तसदीक होने पर निम्न प्रकार शुल्क वसूला जायेगा।

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| 1 | नगर पंचायत के सीवर टैंकर की क्षमता | 4000 लीटर |
| 2 | नगर पंचायत सीमा के भीतर | :- रु 0 8000 / - प्रति फेरा , तथा रु 0 1000 / STP शुल्क , कुल रु 0 9000 / - भवन स्वामी पालिका में शुल्क जमा करेगा। सैप्टिक टैंक में ज्यादा फिकल होने पर दूसरे फेर की स्थिति होने के कारण सम्बन्धित कर्म के द्वारा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पश्चात दूसरे फेरे में 2000 / - रु 0 की छूट प्रदान की जायेगी। |
| 3 | : पालिका सीमा के बाहर | :- रु 0 8000 / - प्रति फेरा , तथा रु 0 1000 / STP शुल्क कुल रु 0 1000 / एवं रु 0 500 प्रति कि 0 मी 0 आधार पर भवन स्वामी पालिका में शुल्क जमा करेगा। सैप्टिक टैंक में जादा फिकल होने पर दुसरे फेर की स्थिति होने के कारण सम्बन्धित कर्म के द्वारा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात दुसरें फेरे में रु 2000.00 की छूट प्रदान जायेगी। |

4:-नगर पंचायत गंगोत्री द्वारा यह भी देखा जायेगा कि यदि कोई सैप्टिक टैंक ज्यादा ही छोटा है . तो निरीक्षण पश्चात तथा यह समाधान हो जाने पर कि सम्बन्धित सैप्टिक टैंक में 4000 लीटर का सीवर टैंक पूर्ण नहीं भर पायेगा उपरोक्त निर्धारित दरों में आवश्यक छूट देकर शुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

8:- मैकेनिजम का निरीक्षण, कियान्वयन और मजबूती देना:

8.1-कोई भी व्यक्ति जो कि एस 0 एम 0 सी 0 / नगरीय स्थानीय संस्था द्वारा अधिकृत है . उसको पूर्ण अधिकार हागा दि . वह सेप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गड्ढे या सामुदायिक / संस्थागत आदि का निरीक्षण करना ।

8.2:-मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है , जुर्माना अलग से लगाया जायेगा और इसस प्राप्त धनराशि नगरपालिका में जमा की जायेगी ।

8.3:- यू 0 एल 0 बी 0 और परिचारक सेप्टिक टैंक के खाली होन का अभिलेख रखेंगे ।

8.4:- अवचेतना कार्यक्रम समय - समय पर चलाया जायेगा , जो कि प्रत्येक व्यक्ति , सरकार या निजी व्यवसायी के सेप्टिक टैंक , बायोडाइजेस्टर , मल निस्तारण सेप्टिक टैंक का , एकत्रीकरण , मशीनरी , परिवहन निष्पादन और सेप्टेज का इलाज हेतु प्रशिक्षण होगा ।

9. दंड :

दंड का ढांचा उपकरण से रहित / अकार्यशील जी ० पी ० एस ० प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायतें , फेकल सलज का एकत्र न करना और सेप्टेज ट्रीटमेन्ट प्लांट / आर.एन.एन . का रजिस्ट्रीकरण न करना । सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाड़ियों का अनुपालन न करना ।

सारणी 3 : दंड

| क्र० स० | शिकायत का प्रकार | दंड या कार्यवाही प्रथम दृष्टया पकड़ी गयी वर्ष में एक बार मल निस्तारण वाहन | दंड या कार्यवाही वर्ष में दुबारा पकड़ी गयी मल निस्तारण वाहन से निस्तारण वाहन सम्बन्धित | दंड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे समय पकड़ी गयी विशेष रूप मल निस्तारण वाहन |
|------------|---------------------------|--|---|---|
| 1- | लोगो की सेवा की शिकायत | 2500 | 5000 | 3 महीने के लिए परमिट सेवा की शिकायत परमिट का निरस्तीकरण |

| | | | | |
|---|---|------|--|---|
| 2 | सेप्टेज / फेकल सलज जैसा कि विशेष कार्यक्षेत्र में खाली न करने पर | 1000 | 6 माह के लिये परमिट को स्थागित करना | 3 महीने के लिए परमिट सेवा की शिकायत परमिट का निरस्तीकरण |
| 3 | पंजीकरण न करना / पंजीकरण का नीवनीकरण न करना | 1000 | 2000 | आर 0 टी 0 ओ 0 को संस्तुति दाहन के पंजीकरण को निरस्त करने हेतु 3 महीने के लिए परमिट को स्थागित करना / परमिट का निरस्तीकरण लिए स्थागित करना |

ह० (अस्पष्ट)
अधिशाली अधिकारी,
नगर पंचायत गंगोत्री,
उत्तरकाशी।

ह० (अस्पष्ट)
प्रभारी अधिकारी,
नगर पंचायत गंगोत्री,
उत्तरकाशी।

ह० (अस्पष्ट)
जिलाधिकारी/प्रशासक,
उत्तरकाशी।